शासन और प्रशासन का ध्येय जनसेवा होना चाहिए- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने वाजपेयी की जयन्ती पर सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई

जयपुर, 25 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 'सुशासन दिवस' के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। शर्मा ने कहा कि स्व. वाजपेयी का जीवन और दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जनसेवा होना चाहिए।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लोकतांत्रिक शासन की आत्मा होती है। विगत 2 वर्षों में हमने 65 लाख से अधिक जन-शिकायतों का निस्तारण किया।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित "सुशासन दिवस" कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास व अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तभी संभव है, जब नियम स्पष्ट हों, अधिकारी संवेदनशील हों और सरकार उत्तरदायी बने। उन्होंने कहा कि सुशासन ऐसी व्यवस्था है, जहां जनता की जरूरतों को समझकर उनको समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सुशासन का आधार विश्वास, संवाद और परिणाम के तीन स्तंभों पर टिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लोकतांत्रिक शासन की आत्मा होती है। प्रदेश में राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई और मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं की प्रभावी सुनवाई कर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में हमने 65 लाख से अधिक जन-शिकायतों का निस्तारण किया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भारत बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। आमजन का सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में विश्वास दृढ़ हुआ है। इस दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार सहित, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम से वीसी के जरिए जिला, उपखंड एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी एवं कार्मिक भी जुड़े। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी को मुख्यमंत्री निवास पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

स्टालिन ने प्रधानमंत्री के क्रिसमस समारोह में शामिल होने की आलोचना की

चेन्नई, 25 दिसंबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले की आ रही खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का क्रिसमस समारोह में शामिल होना परेशान करने वाला है।

स्टालिन ने जबलपुर और रायपुर में अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि

- **तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों के बीच प्रधानमंत्री का कदम परेशान करने वाला है।**

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के सत्ता में आने के बाद, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में 74 प्रतिशत की वृद्धि गंभीर खतरे का संकेत है। उन्होंने मणिपुर के बाद जबलपुर, रायपुर और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को उन सभी लोगों के लिए अस्वीकार्य बताया, जो सद्भाव को महत्व देते हैं।

स्टालिन ने कहा कि बहुमत की सच्ची ताकत और चरित्र यह सुनिश्चित करने में है कि अल्पसंख्यक बिना किसी डर के रहें। उन्होंने समाज को बांटने वाले दंगाई समूहों पर अंकुश लगाने की वकालत करते हुए, इसे दृढ़ संकल्प के साथ तत्काल लागू किए जाने की जरूरत बताई।

प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस पर चर्च गए और प्रार्थना सभा में भाग लिया

दिल्ली के बिशप डॉ पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना सभा रखवाई तथा चर्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास से केवल दो स्थित किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली के कथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की मॉर्निंग सर्विस में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

सेवा में प्रार्थनाएँ, क्रिसमस कैरोल, भजन और दिल्ली के बिशप राइट रेव. डॉ. पॉल स्वरुप द्वारा प्रधानमंत्री के लिए की गई विशेष प्रार्थना शामिल थी।

इससे पहले, मोदी ने गुरुवार को लोगों को गर्मजोशी से क्रिसमस की शुभकामनाएँ दीं तथा इस अवसर पर शांति, सहानुभूति और उम्मीद की कामना की।

बिशप ने उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में चर्चों और ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों का स्मरण दिलाया और इन हमलों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएँ, तथा शांति, सहानुभूति और आशा की कामना की। ईसा मसीह की शिक्षाएँ हमारे समाज में सद्भावना को मजबूत करें।"

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ईसा मसीह की शिक्षाओं से जुड़े प्रेम, सेवा और भाईचारे की शाश्वत मूल्यों को रेखांकित किया और उनके सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता को उजागर किया है। देशभर के शहरों को दीपों, घंटियों और हारों से सजाया गया है, क्योंकि लोग क्रिसमस की खुशी में डूबे हुए हैं।

- **प्र.मंत्री ने एक्स पर देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं और शांति, सद्भाव की कामना की तथा आज के दौर में ईसा मसीह के प्रेम, सेवा और भाईचारे के संदेश की महत्ता बताई।**
- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर एक पोस्ट में क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा, हम सभी को ईसा मसीह के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए।**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर एक पोस्ट साझा करके अपनी शुभकामनाएँ दीं। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर, मैं सभी नागरिकों, विशेषकर ईसाई समुदाय के भाइयों और बहनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ। क्रिसमस, खुशी और उत्साह का त्योहार है, जो प्रेम और सहानुभूति का संदेश देता है। यह हमें ईसा मसीह द्वारा मानवता के कल्याण के लिए किए गए बलिदान की याद दिलाता है। यह पवित्र अवसर हमें समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। आइए, हम ईसा मसीह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करें जो दयालुता और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे।"

बाज़ार की दुकानों को सांता क्लॉज की स्लेे, घंटियाँ, फ्रिल्स, सजावटी हार, चमकते सितारे और क्रिसमस के पेड़ों से सजाया गया है। पूरे देश में त्योहार का जबरदस्त माहौल है और हर कोई आगामी छुट्टियों की तैयारी में व्यस्त है।

'सैन्यकर्मी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं'

नयी दिल्ली, 25 दिसम्बर। सेना ने डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल के मामले में अधिकारियों और सैनिकों के लिए अपनी सोशल मीडिया नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन्हें इंस्टाग्राम और एक्स सहित, कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सशर्त पहुंच की अनुमति दी है।

सैन्यकर्मियों को यह अनुमति कड़े दिशा-निर्देशों के साथ दी गई है। उन्हें इन

- **सेना ने सोशल मीडिया संबंधी नियमों में भारी बदलाव किया**

प्लेटफार्म पर केवल सामग्री देखने और निगरानी करने की अनुमति होगी, लेकिन अपनी ओर से पोस्ट करने, टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बातचीत पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि संचालन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सेना द्वारा इस बारे में जारी पत्र में कहा गया है कि सैन्यकर्मियों को तत्काल प्रभाव से केवल सामग्री देखने और निगरानी के उद्देश्य से इंस्टाग्राम के उपयोग की अनुमति दी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंस्टाग्राम पर कोई टिप्पणी या विचार साझा नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया के सीमित उपयोग को स्पष्ट करते हुए सेना ने स्काइप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल का उपयोग सामान्य प्रकृति की अवर्गीकृत जानकारी के आदान-प्रदान के लिए करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि सामग्री का आदान-प्रदान केवल परिचित व्यक्तियों के साथ ही किया जाए और प्राप्तकर्ता की सही पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी।

सरकार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखना चाहिए? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ एक्शन लेने का पूरा हक है। अगर कोई भी इस देश में अवैध तरीके से रह रहा है या वीजा की अवधि से अधिक वक्त तक ठहरा हुआ है, तो सरकार के पास उसको डिपोर्ट करने का अधिकार है। इसलिए सरकार को अपना काम करने दें।

वहीं, कानून के पालन पर जोर देते हुए शशि थरूर ने मानवीय दृष्टिकोण और संतुलित तरीके को अपनाने की जरूरत भी बताई, खासकर उन सेंसटिव सीमा-पार मामलों में, जिनमें मानवीय और राजनीतिक दोनों पहलू जुड़े होते हैं।

इसके अलावा, कांग्रेस नेता थरूर ने भारत सरकार के बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंडिया में रहने देने के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने इसे मानवीय मूल्यों पर आधारित

- **कांग्रेस नेता शशि थरूर ने घुसपैठियों के खिलाफ केन्द्र सरकार का समर्थन किया**

कदम बताया। थरूर ने कहा कि भारत ने उनको वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं करके सही मानवीय भावना के तहत काम किया। साथ ही, उन्होंने शेख हसीना के भारत के साथ पुराने संबंधों और वर्षों तक देश की एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर उनके रोल का भी जिक्र किया। थरूर के मुताबिक, डिपोर्टेशन या प्रत्यर्पण से जुड़े केस जटिल कानूनी ढांचे में आते हैं, जिनमें संधियां और उनके अपवाद शामिल होते हैं। इन पर सावधानी से विचार जरूरी होता है। ऐसे फैसले सरकार के विवेक पर छोड़ देने चाहिए।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैठक के तुरंत बाद बुलाई है।

सलाहकार परिषद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे । ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक के एजेंडे में ओबीसी कांग्रेस के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और हैदराबाद में होने वाली आगामी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक के लिए विशिष्ट कार्यक्रम को अंतिम रूप देना शामिल है। इन चर्चाओं में देशभर में ओबीसी समुदाय के लिए पार्टी की पहुंच और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत प्रदान करना शामिल है।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगलवार देर रात चली तेज हवाओं के कारण प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। राजधानी में 22 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली हवाओं ने एक्यूआई को काफी हद तक कम करने में मदद की। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ था । इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएसक्यूएम) ने कल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत स्टेज-4 प्रतिबंध हटा लिया है। यह फैसला रात तेज हवाओं के चलने के कारण कुछ घंटों बाद लिया गया। हालांकि, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में गिरावट आने के आसार हैं। वहीं, ग्रैप के स्टेज-एक, दो और तीन के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे।

ट्रक से टक्कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2.30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सीबर्ड ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गई। बस में तुरंत आग लग गई। उस समय यात्री सो रहे थे। इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला।

पुलिस का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक किए थे। इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए हैं। उनके परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जले हुए शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा।

ईस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रविकांत गौड़ा ने बताया कि बस के ड्राइवर और क्लीनर बच गए हैं, जबकि ट्रक के ड्राइवर-क्लीनर की मौत हो गई है। कई यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। घायल यात्रियों को तुमकुरु जिले में शिरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो यात्री गंभीर हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है।

हादसे का शिकार हुए बस के ड्राइवर ने पुलिस को बताया है कि उसने सामने से आ रहे ओवरस्पीड ट्रक को देखकर अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की बर्बर हत्या

भीड़ ने पीट-पीट कर युवक को मार डाला

ढाका, 25 दिसंबर। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, युवक पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था।

यह घटना रात करीब 11 बजे कलीमोहर यूनियन के होसेंदंगा गांव में हुई, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पांगशा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक देब्रत सरकार ने बताया कि मृतक की पहचान अमृत मंडल, उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान पुलिस ने सम्राट के एक साथी

- **युवक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई आरोप लगाया गया है कि वह वसूली करता था इसलिए गुस्साई भीड़ ने उसे मार डाला।**
- **पुलिस ने बताया कि उसने अमृत मंडल को भीड़ से बचाया वह बुरी तरह घायल था, अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई।**

मोहम्मद सलीम को मौके से गिरफ्तार किया। सलीम के पास से पुलिस ने दो हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सम्राट को गंभीर हालत में भीड़ से बचाया।

पुलिस ने बताया कि सम्राट की बिगड़ती हालात को देखते हए उसे तुरंत पांगशा उपजिला स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रात करीब 2 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक बरामद की और उसे हिरासत में ले लिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजबाड़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। इसके बाद 18 दिसंबर को हादी का सिंगापुर में निधन हो गया और तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके ठीक बाद चटगांव में एक हिंदू शख्स की लिंचिंग की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।

अब बांग्लादेश के नए राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के एक नेता पर भी हमला हुआ है। सोमवार को एनसीपी के मोहम्मद मुतालिब सिकदर को खुलना में गोली मार दी गई। इस हमले में सिकदर के सिर पर चोट आई है। बताया गया है कि उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भारत ने किया के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

नई दिल्ली, 25 दिसंबर। भारत ने 23 दिसंबर 2025 को एक गोपनीय पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) का सफल परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि ये परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया।

दरअसल, यह परीक्षण परमाणु-सक्षम के-4 मिसाइल का था। यह अरिहंत-क्लास पनडुब्बी से लॉन्च की गई। इस परीक्षण को लेकर पहले से कोई घोषणा नहीं की गई थी। वहीं, एनओटीएएम भी रद किया गया था,

- **सूत्रों के अनुसार, यह गोपनीय परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया**

जिससे गोपनीयता बनाई रखी जा सके। दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में चीनी निगरानी जहाज मौजूद थे।

बता दें कि यह परीक्षण भारत की समुद्र आधारित न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत कर रहा है, जिससे सेकंड स्ट्राइक की क्षमता सुनिश्चित होती है। इस मिसाइल से दुश्मन के पहले हमले के बाद ही जवाबी कार्रवाई की गारंटी भी मिल जाती है।

इस के-4 मिसाइल की सबसे खास बात है कि यह स्वदेशी के- सीरीज की मिसाइल है। यह डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई है। ये मिसाइल खास तौर पर अरिहंत-क्लास परमाणु पनडुब्बियों के लिए ही डिजाइन की गई है।

इस मिसाइल की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। वहीं, इसकी लंबाई 12 मीटर के करीब है। व्यास की बात करें तो वह 1.3 मीटर है। मिसाइल का वजन 17-20 टन का है। पेलोड की बात करें तो यह 2 टन तक है। इसमें पानी के नीचे से लॉन्च (कोल्ड लॉन्च सिस्टम), 3डी मैन्यूवर करने में सक्षम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से बचने की ताकत भी है।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब देने के लिए कहा है।

वेनेज़ुएला के प्रकरण में ट्रंप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। इससे उसे वैश्विक तेल बाज़ार और आपूर्ति पर बहुत बडी ताक़त मिलेगी और वह तेल की क़ीमतों को भी नियंत्रित कर सकेगा।

आख़िरकार, वेनेज़ुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अगर अमेरिका इस देश से कोई समझौता कर लेता है तो उसकी तेल कंपनियों के लिए वहाँ काम करने का एक बहुत बड़ा मैदान खुल जाएगा। इसी प्रक्रिया में अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को दूर रखने में भी कामयाब हो सकेगा।

इसके अलावा, कुछ हद तक, तेल से होने वाली कमाई मदुरो के नेतृत्व वाली सरकार के पास वापस जाने देने से अमेरिका उस शासन को जिंदा रहने भर की "ऑक्सीजन" दे रहा है।

अमेरिका का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर आर्थिक पाबंदियाँ और तेल आय पूरी तरह रोकने से वेनेज़ुएला सरकार गिर गई, तो कहीं चीन वहाँ घुसकर उसके तेल भंडार पर कब्जा न कर ले। यह वो डरावना सपना है, जिसके बारे में अमेरिका सोचना भी नहीं चाहता। इस समय अमेरिका अपनी पूरी विदेश नीति को नए सिरे से गढ़ रहा है और सदियों पुराने "मनरो सिद्धांत" को फिर से ज़िंदा कर रहा है। उन्नीसवीं सदी के अमेरिकी राष्ट्रपति

- **इस स्कीम से अमेरिका ने चीन पर भी वेनेज़ुएला में प्रवेश पर एक तरह से नियंत्रण लगा रखा है।**
- **ट्रंप, वेनेज़ुएला को उतना ही ऑयल निकालने दे रहे हैं, जिससे उसकी इकॉनमी ध्वस्त न हो जाए और केवल कुछ सांस ले सके।**
- **अगर इकॉनमी पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगी तो चीन को वेनेज़ुएला में प्रवेश करने का बहाना मिल सकता है, क्योंकि चीन ने वेनेज़ुएला के "इंफ्रास्ट्रक्चर" में काफी पैसा इनवैस्ट कर रखा है।**
- **"मनरो डॉक्ट्रिन" के तहत ही अमेरिका ने रूस को क्यूबा में अपनी मिसाइल्स लगाने नहीं दी थी, 1960 के दशक में और रूस को क्यूबा से मिसाइल वापस ले जानी पड़ी थी।**

हर्बर्ट हेनरी मनरो द्वारा रखे गए इस सिद्धांत के मुताबिक, अमेरिका को अपने प्रभाव क्षेत्र में पूरी तरह प्रभुत्व रखना चाहिए, यानी अपने "हैमिस्फियर" में सर्वोच्च शक्ति होना चाहिए। अगर वेनेज़ुएला में सत्ता का खालीपन पैदा होता है और अनिश्चितता के बीच चीन को वहाँ घुसने का मौक़ा मिल जाता है, तो उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इससे बेहतर यह होगा कि अमेरिकी कंपनियाँ तेल संसाधनों पर कब्जा करके और उन्हें कंट्रोल करके पूरे देश पर पिछले दरवाज़े से कब्जा कर लें।

इसी संदर्भ में ट्रंप बार-बार वेनेज़ुएला द्वारा तेल संसाधनों के राष्ट्रीयकरण और ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों को रोकने को अमेरिका के ख़िलाफ़ "चोरी" बताते रहे हैं। वे चाहते हैं कि ये संसाधन फिर से अमेरिकी तेल कंपनियों के हाथ में आएँ। लेकिन ये कदम और सिद्धांत राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्णय के मौजूदा सिद्धांतों के खिलाफ हैं। मगर इन मूल्यों और मानकों की परवाह किसे है, जब बड़ी ताक़तों के हित पूरे हो रहे हों। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ तो इतनी खुली आक्रामकता दिखाई है, लेकिन उसने कभी रूसी टैंकरों के, तेल ले जाने वाले "गुप्त बेड़ों" के ख़िलाफ़ ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया है। अमेरिका की इस खुली आक्रामकता के खिलाफ किसी ने ज्यादा आवाज़ भी नहीं उठाई है।

यह सिर्फ "पावर स्पीक" है, जो एक्शन में दिख रही है।

दिल्ली में 5 रूपए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजौरी गार्डन, नरेला, बवाना और अन्य स्थान शामिल हैं। बाकी 55 कैंटीनों का उद्घाटन अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। ये कैंटीन दिन में लगभग 500 लोगों को दो भोजन देंगी - दोपहर का भोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और रात का खाना शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। दिल्ली सरकार ने भोजन वितरण के लिए मैन्युअल कूपन की जगह एक डिजिटल टोकन प्रणाली शुरू की है। सभी केन्द्रों की निगरानी "दिल्ली अरबन शेल्टर इन्प्रूवमैंट बोर्ड" (डीयूएसआईबी) के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जाएगी।

अरावली पर्वत श्रंखला के किसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब धरोहर इमारतें नहीं रहेंगी और इसलिए उन्हें सड़कें और खनन परियोजनाओं के लिए नष्ट करना होगा? यही हम अरावली के साथ कर रहे हैं।

एक प्रेस विज्ञप्ति में इस मामले को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, जिसमें कहा गया है, "अरावली रेंज को ऐसे सभी भूमि रूपों के रूप में समझाया गया है कि वे भू आकृतियां (लैंडफॉर्म्स), जो 100 मीटर से अधिक है, उन्हें ही अरावली माना जाएगा, ऐसी दो पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में है तो उनके बीच के भाग को भी अरावली माना जाएगा। इसमें उनकी ढलानें आदि भी शामिल हैं।

इसके बावजूद, 100 मीटर शब्द जस का तस है।

यहां चार सवाल दिए गए हैं, जो अभी भी अनुत्तिरत हैं:

1. मंत्री ने पहाड़ की ऊंचाई की परिभाषा को मीन सी लेवल से स्थानीय राहत में क्यों बदल दिया?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय (जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत परिभाषा पर आधारित था) के पैराग्राफ 31 में कहा गया है कि "भारत सरकार इसलिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की परिभाषा का उपयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि यह अरावली के बड़े हिस्से को पर्वत श्रंखला के दायरे से बाहर कर देगा।" जबकि वास्तव में स्थानीय राहत के आधार पर ऊंचाई का मानदंड उपयोग में लाने से अरावली का बड़ा क्षेत्र बाहर हो जाएगा।

- **उदाहरण के लिए मानेसर कस्बा ही "मीन सी लैवल" से 265 मीटर ऊंचाई पर बसा है तथा वहाँ के पर्वत की ऊंचाई 315 मीटर है और अगर मानेसर कस्बे की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई से घटा दी जाए तो पर्वत की ऊंचाई 50 मीटर आंकी जाएगी, जो 100 मीटर की सीमा से काफी कम है। अतः, वहाँ के पर्वत को पूरी तरह तोड़ा जा सकेगा।**

2. जब एक पहाड़ी की ऊंचाई केवल 40 मीटर हो, लेकिन वह तेंदुए, चिंकारा या एक संकटग्रस्त वनस्पति प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, तो क्या होगा? और अगर ऐसा है, तो ऊंचाई को मानदंड के रूप में क्यों पेश किया गया? क्या ऐसे क्षेत्र अब अरावली का हिस्सा नहीं माने जाएंगे?

3. जो बात मंत्री ने साझा नहीं की, वह यह है कि हरियाणा राज्य के लिए वन क्षेत्र की परिभाषा को अगस्त 2025 में भी बदला गया है, ताकि अरावली में खनन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

हरियाणा में नई परिभाषा को अगस्त 2025 में अधिसूचित किया गया। इसके अनुसार, 5 हैक्टयर क्षेत्र अलग-अलग या दो हैक्टेयर लगातार और 40 प्रतिशत कैनपी डैंसिटी वाला क्षेत्र ही जंगल माना जाएगा। पर सेमी एरिड व एरिड ज़ोन, जहाँ 40 प्रतिशत कैनपी डैंसिटी संभव नहीं है, वे अब वन क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। जब मंत्री कहते हैं कि अरावली का 90 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, तब वे हाल ही में किए गए उन कानूनी बदलावों का जिक्र नहीं कर हैं, जो बड़े क्षेत्र को खनन के लिए खोल देंगे।

4. अब, यहां तर्क और जटिल हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र हैं, जो अब अरावली से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, जैसे- मानेसर, जो 265 मीटर एमएसएल ऊपर है, मानेसर की सबसे ऊंची पहाड़ी 315 मीटर ऊंची है, लोकल रिलीफ के आधार पर पहाड़ी की ऊंचाई मात्र 50 मीटर है अर्थात यह अरावली का हिस्सा नहीं रहेगा। इसी प्रकार की स्थिति पंचगाँव (286 मीटर एमएसएल) खेराला, हरियाणा (257 मीटर एमएसएल), गैरतपुर, (250 मीटर एमएसएल) में हैं, यहाँ जो पहाड़ियां है, लोकल रिलीफ के आधार पर 100 मीटर से काफी कम हैं, तो इन क्षेत्रों को अब अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिया जाएगा।

भूगर्भीय विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचाई हमेशा मीन सी लेवल (एमएसएल) से मापी जाती है, न कि आसपास की ज़मीन से। मीन सी लेवल दुनियाभर में सामान्य रूप से स्वीकृत मानक है, तो मंत्री यह क्यों नहीं समझ रहे कि वे ऊंचाई को स्थानीय राहत के आधार पर क्यों माप रहे हैं?

मंत्री के स्पष्टीकरण पर अरावली विरासत जन अभियान के एक्टिविस्टों ने स्पष्टीकरण की विसंगतियों को उजागर किया है और सवाल किया है कि क्या मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि अरावली के सभी पहाड़ों को उनकी ऊंचाई की परवाह किए बिना संरक्षण मिलेगा?

अरावली को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, ताकि न केवल इसकी जैवविविधता बच सके, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोग भी इस प्रभाव से बच सकें, जो पहले से ही शुद्ध हवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908